Rate of increase in money supply

435. SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI YASHWANT SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the rate of increase in money supply during January to June, 1990;

(b) what was the figure for the corresponding period last year; and

(c) what is Government's thinking with respect thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) During January-June, 1990 money supply (M3) recorded an increase of 7.3 per cent as against 6.9 per cent increase in January-June, 1989.

(c) The stance of the monetary policy is to moderate the rate of growth in money supply in the current financial year to well below the rate recorded in the last financial year through general and selective credit control measures.

Distribution of Central Revenues to States

436. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) What steps Government propose to take to ensure fair share of Central revenues to States;

(b) whether Government also propose to give more financial powers to the States; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Based on the recommendations of the Finance Commission, Govt, of India gives share in Central taxes as well as grants to the States. Besides, Central assistance for State Plans and Centrally Sponsored Schemes is also provided. Central Government also provides loans to States to the extent of 75% of net collections of small savings.

(b) and (c) Some States had suggested to the Commission on Centre-State Relations that their fiscal powers may be enlarged by empowering them to levy taxes and duties included in Articles 268 and 269 of the Constitution; transfer of residuary powers of taxation to the States; and removing relaxing the limitations on their powers to raise resources including transfer to them of powers of taxation in regard to certain commodities. The recommendations of the commission in this regard are under consideration of the Government.

राज्य व्यापार निगम द्वारा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम का अधिग्रहण

437. **श्री बलराम सिंह यादव:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार निगम ने हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और इसके क्या कारण हैं तथा क्या राज्य व्यापार निगम अब देश के खुदरा-बाजार में वनस्पति तेलों के विपणन में सक्रिय भूमिका निभायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पिछले छह महीने के दौरान उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का भरा जाना

438. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 के प्रारम्भ में

उच्चतम न्यायालय और देश के अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त पदों की न्यायालयवार संख्या कितनी है और क्या सरकार ने पिछले छह महीने के दौरान इन रिक्त पदों को भरा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और शेष रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अंतिरिक्त प्रभार ((श्री दिनेश गोस्वामी): (क) से (ग) तारीख 1.1.1990 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों और तारीख 1.1.1990 से तारीख 7.8.1990 तक देश के विभिन्न न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की की गयी नियुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया चल रही है किन्तु वह तारीख बताना संभव नहीं है जब तक ये भर दिए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	तारीख 01.01.90 को रिक्त पदों की संख्या	तारीख 01.01.90 से 07.08.90 तक की गई नयी नियुक्तियां
1.	इलाहाबाद	11	9
2.	आंध्र प्रदेश	9	6
3.	मुम्बई	6	9
4.	कलकत्ता	3	6
5.	दिल्ली	6	6
6.	गुवाहाटी		
7.	गुजरात	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	2	3
9.	जम्मू-कश्मीर	2	
10.	कर्नाटक	6	9
11.	केरल	2	
12.	मध्य प्रदेश	7	6
13.	मद्रास	6	8
14.	उड़ीसा	1	
15.	पटना	7	11
16.	पंजाब और हरियाणा	5	4
17.	राजस्थान	4	7
18.	सिक्किम	2	
	योग :	87	93
II	उच्चतम न्यायालय	2	1

सीमाशुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

439. **श्री अजीत जोगी:**
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दस वर्षों से भी अधिक समय से दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं;